भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1966
दिनांक 11 मार्च, 2025 / 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आपदाओं से लोगों को बचाने हेतु नवाचारी पद्धतियां

†1966. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लोगों को विभिन्न आपदाओं, चाहे वे प्राकृतिक हों अथवा मानव निर्मित हों, से बचाने के लिए विभिन्न नवाचारी पद्धतियां अपनाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी आपदाओं से निपटने में अन्य देशों की तुलना में हमारे देश का स्थान अथवा रैंक क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में अन्य विकसित देशों में कोई नई/बेहतर पद्धति अपनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि आपदा प्रबंधन चक्र में तैयारी, प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण तथा नवीन तरीकों, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपयोग से शमन जैसे सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके। पिछले दशक के दौरान, भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नवीन विधियाँ इस प्रकार हैं:-

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) विकसित की है। योजना को 2019 में संशोधित किया गया और इसे दस सूत्री एजेंडे के साथ जोड़ा गया। संशोधित एनडीएमपी केंद्रीय और राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1966, दिनांक 11.03.2025

ii. एनडीएमए ने विभिन्न विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर खतरा विशिष्ट आपदा के प्रबंधन के लिए अड़तीस (38) दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iii. एनडीएमए ने चक्रवात जोखिम शमन और प्रतिक्रिया योजना के लिए एक वेब-आधारित डायनेमिक कम्पोजिट जोखिम एटलस और निर्णय समर्थन प्रणाली (वेब-डीसीआरए और डीएसएस टूल) विकसित किया है। इस टूल का हाल के चक्रवातों जैसे बिपरजॉय और मिचौंग में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

iv. राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रवण राज्यों और जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ खतरा एटलस विकसित किए गए हैं।

v. एनआरएससी ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 28,000 हिमनद झीलों का एक व्यापक डेटा सेट तैयार किया है।

vi. भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने एक डिजिटल एटलस विकसित किया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परियोजना की तैयारी में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है।

vii. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) सभी प्रभावित/संभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चक्रवातों सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है।

viii. आईएमडी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर विकसित होने वाले चक्रवातों की निगरानी के लिए उपग्रहों, रडार और पारंपरिक और स्वचालित मौसम स्टेशनों से गुणवत्ता अवलोकन का एक सूट का उपयोग करता है। इसमें INSAT 3D, 3DR और SCATSAT उपग्रह, तट के साथ डॉपलर मौसम रडार (DWR) और तटीय स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS), उच्च वायु गति रिकॉर्डर, स्वचालित वर्षा गेज (ARG), मौसम संबंधी बुआ और जहाज शामिल हैं। लोगों/किसानों को समय पर पूर्व चेतावनी और अलर्ट देने के लिए दामिनी, मौसम, मेघदूत आदि जैसे कई अन्य नए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं।

ix. लोगों/किसानों तक समय पर पूर्व चेतावनी और अलर्ट पहुंचाने के लिए दामिनी, मौसम, मेघदूत आदि जैसे कई अन्य नए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं।

x. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के तहत, तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जो हाल के चक्रवातों के दौरान तटीय समुदाय को अलर्ट प्रसारित करने में काफी मददगार साबित हुई हैं।

xi. सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत के नागरिकों को आपदाओं से संबंधित भू-लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों/अलर्ट के प्रसार के लिए 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली' लागू की गई है। इसके लिए एसएमएस, टीवी, रेडियो, कोस्टल सायरन, सेल प्रसारण, इंटरनेट (आरएसएस फीड और ब्राउज़र नोटिफिकेशन), गगन और नाविक के सैटेलाइट रिसीवर आदि जैसे विभिन्न प्रसार माध्यमों का उपयोग किया गया है। इसके लिए सभी चेतावनी एजेंसियों [भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)] को एकीकृत किया गया है।

xii. CAP प्रणाली में, विभिन्न आपदाओं से संबंधित अलर्ट IMD, CWC, INCOIS, DGRE और FSI जैसी अलर्ट जनरेटिंग एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के SDMA द्वारा मॉडरेट किए जाते हैं। अलर्ट क्षेत्रीय भाषाओं में भू-लक्षित क्षेत्रों को भेजे जाते हैं। अब तक 4500 करोड़ से अधिक अलर्ट संदेश प्रसारित किए जा चुके हैं।

xiii. माननीय प्रधानमंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल संकट नंबर' के विजन को लागू करने के लिए मौजूदा एकल नंबर "112" के साथ "ईआरएसएस का विस्तार" परियोजना को लागू किया गया है, ताकि आपदाओं से संबंधित आपातकालीन कॉल को पूरा किया जा सके।

xiv. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के तत्वावधान में भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) स्थापित किया गया है, ताकि आपदा लचीलेपन में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की भूमिका को उजागर किया जा सके और विभिन्न स्तरों पर इसके एकीकरण के साथ डीआरआर के लिए मॉडल पाठ्यक्रम विकसित किया जा सके। आईयूआईएनडीआरआर शिक्षा और नीति के बीच इंटरफेस के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ज्ञान उत्पादों के सहयोगी विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब तक, 330 से अधिक विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं।

xv. 16 बटालियनों और 28 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्रों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) विभिन्न आपदाओं का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित हैं।

xvi. लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एनडीएमए और एनडीआरएफ द्वारा नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

xvii. वैश्विक स्तर पर, भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है।

xviii. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में किया गया था। अब तक, 42 देशों और 7 अन्य संगठनों ने इसके चार्टर का समर्थन किया है और सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। सीडीआरआई वर्तमान में 13 छोटे द्वीप विकासशील देशों को उनके बुनियादी ढांचे की प्रणालियों को आपदा रोधी बनाने में सहायता कर रहा है। इसके अलावा, सीडीआरआई बिजली और दूरसंचार जैसे विशिष्ट विकास क्षेत्रों में आपदा रोधी क्षमता को एकीकृत करने पर काम कर रहा है।

xix. भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक कार्य समूह की स्थापना की गई थी, जिसमे डी. आर. आर. के पांच प्राथमिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया ।

xx. सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) जैसे कई क्षेत्रीय संगठनों के तहत सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। इन संगठनों के साथ, भारत ने संयुक्त अभ्यास किए हैं और साथ ही आपदा प्रबंधन में अच्छे तरीकों को साझा करने में सुविधा प्रदान की है।

xxi. यूएनडीआरआर द्वारा भारत को दुनिया के उन पाँच देशों में से एक माना जाता है जो तटीय क्षेत्रों के लिए जोखिम, उन पर आने वाली लहरों की ऊँचाई और यहाँ तक कि भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (आईटीईडब्ल्यूसी) के माध्यम से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए 'वास्तविक समय' में कमज़ोर इमारतों की पहचान करने का पूर्वानुमान लगाते हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1966, दिनांक 11.03.2025

xxii. सरकार आपदा प्रभावित देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान कर रही है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के तहत, भारत सरकार ने फरवरी, 2023 में भीषण भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया को राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और चिकित्सा दल भेजकर तत्काल मदद की थी।

*****